tion of unemployed educated and uneducated both men and women reached to a point of grave culmination. The encouragement and patronage extended to some other backward areas are not extended to this distant southernmost part of our country. To obviate the prevailing unemployment and economic deterioration in this part it is just, appropriate, proper and equitable to set up an ancillary unit of H.M.T. or any other public undertaking and establish an industrial complex in this long awaited unnoticed needy place. So Government may be pleased to take immediate steps for the establishment of an ancillary unit of H.M.T. or any other public undertaking unit and establish an industrial complex in Kanyakumari District.

(vi) RETRENCHMENT OF WORKERS IN THE BEAS-SUTLEJ PROJECT IN HIMACHAL PRADESH AND NEED TO PROVIDE THEM EMPLOYMENT

SHRI VIRBHADRA SINGH (Mandi): Consequent to the completion of the Beas Sutlej Project in Himachal Pradesh thousands of work-charged employees of the Project have been retrenched. At present about 6,000 work-charged employees are still employed and they are also facing retrenchment progressivley. Most of these employees are very senior in their trade and have put in decades of service. It will be a great hardship to them if they are at this stage thrown out of employment. This will also be against the declared policy of the Government not to retrench them without providing alternative employment. I, therefore, urge upon the Government to stop further retrenchment in the Project till such time the workers rendered surplus are provided with alternative employment.

A large number of people lost their homes and lands for the construction of the Project. They were paid very nominal compensation for their most valuable lands. They were assured that at least one member of their family would be provided with permanent employment in the Project. I am sorry to point out that this assurance is not being observed in practice. Many oustees who are working in the Project have already been retrenched. Those who are still working there are facing retrenchment along with other work charged employees. No special consideration is being shown to the oustees. It is most unfari and contrary to the assurance given by the Government from time to time.

I, therefore, request the Government that the oustees may be given priority in the matter of permanent employment in the Bhakra Beas Management Board, the agency responsible for looking after the completed project in consonance with the declared policy of the Government in this respect.

(vii) SOILED AND MUTILATED CURRENCY NOTES IN STATE BANK OF INDIA, BELGAUM.

श्रीमती संयोगिता राणे (पाणाजी) : आजकल बैंकों में गंदे विकृत और कटे फटे नोट प्राय: मिल रहे हैं । इससे जन साधारण को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । छोटे दुकानदार इन्हें लेने में कतराते हैं क्योंकि इन नोटों के अधिक क्षतिग्रस्त होने से उनकी कठिनाइयां बढ़ जाती हैं । इन पुराने और कमजोर नोटों के प्रश्न को ले कर दुकानदार और ग्राहकों में प्राय: कहा सुनी और गर्मा गर्मी देखने को मिलती है । हाल ही में बेलगाम स्थित स्टेट बैंक आफ इंडिया की ब्रांच में नोटों के भारी बंडल देखने को मिले जो कमजोर और दुर्गन्ध से परिपूर्ण थे । वित्त मंत्रालय से मेरा अनुरोध है कि बेलगाम स्थित बैंक में नोटों की इतनी खराब स्थिति के कारण का पता लगाए । इस के लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी है और क्या उपरोक्त बैंक में इतनी व्यवस्था भी नहीं है कि मौसम और वर्षा की खराबी से इन नोटों को सड़ने से

[श्रीमती संयोगिता राणे]

बचाया जा सके ? मुझे विश्वास है कि बैंकों में नोटों को सुरक्षित रखने उन्हें स्वच्छ हालत में बनाए रखने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाएंगे ताकि जन साधारण को कठिनाई न हो ।

(viii) NEED FOR LEGISLATION FOR EXERCISING CENTRAL CONTROL IN THE APPOINTMENTS OF V.C., PROFESSOR, ETC. IN ALL UNIVERSITIES.

प्रो. निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष जी, शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण विषय जो राज्य सरकारों के पास था, आज समवर्ती सूची का विषय बन गया है । अतः इस नोक झोंक के विषय पर केन्द्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि शिक्षा ही राष्ट्रीय विकास की धुरी है । इसके माध्यम से ही राष्ट्रीय एकीकरण की बात सोची जा सकती है । पर दुर्भाग्य से भारतीय शिक्षा व्यवस्था आज नई समस्याओं से घिरी हुई है ।

उसमें प्रमुख यह है कि शिक्षा में एकरूपता नहीं । शिक्षा प्रान्तीयता भाषा, धर्म, जाति और वर्ग की संकीर्णता से घिर कर विकृतता की ओर बढ़ रही है । विश्वविद्यालय प्रांगण में लड़ाई झगड़े, वाकआउट आदि विषय आम बात हो गई है । केन्द्र सरकार यू. जी. सी. के माध्यम से करोड़ों रुपयों का अनुदान विश्वविद्यालयों को देती है पर शिक्षा व्यवस्था पर नियंत्रण नहीं । यूनिवर्सिटी की आटोनामी के नाम पर जो धांधलियां होती है, वह सभी जानते हैं ।

शिक्षा जब समवर्ती सूची का विषय है फिर क्यों नहीं शिक्षा मंत्रालय उपकुलपति, प्रोफेसर तथा रीडर्स की नियुक्ति जैसे विषय को अपने हाथ में लेता है । अंत में शिक्षा मंत्रालय का ध्यान इस अतिमहत्व के महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि देश की सभी यूनिवर्सिटीज के उपकुलपति, प्रोफेसर, रीडर की नियुक्तियां केन्द्रीय सरकार के माध्यम से हों, न कि राज्य सरकारों के माध्यम से । मेरे प्रान्त राजस्थान की 3 यूनिवर्सिटीज जयपुर, जोधपुर तथा राजस्थान विश्वविद्यालय आज समूहों में विभक्त हैं । वी. सी. के पक्ष तथा विपक्ष के समूह हो आये दिन इन शिक्षा के पवित्र स्थलों की शांति भंग किये हुए हैं । यही हाल सम्पूर्ण देश के सभी विश्वविद्यालयों का है । अतः केन्द्रीय सरकार विशविद्यालय के शिक्षा व्यवस्था पर नियंत्रण रखने के लिये तथा राष्ट्रीय एकीकरण और उपरोक्त विषय की गम्भीरता को समझते हुए तुरन्त कोई बिल इसी सत्र में सदन में, अब सम्भव नहीं, अगले सत्र में पेश करे कि सभी विश्वविद्यालय की नियुक्तियों केन्द्र करेगा । वी. सी., तथा प्रोफेसर, रीडर का स्थानान्तरण भी आवश्यकतानुसार एक विश्वविद्यालय से दूसरे में हो सकेगा तभी हम शिक्षा में एकरूपता तथा राष्ट्रीय एकीकरण की बात सोच सकेंगे ।

(ix) NEED TO DESPATCH CENTRAL POLICE FORCE AT SHIRPUR NEAR AKOLA IN MAHARASHTRA TO SAVE RELIGIOUS PEOPLE FROM ATTACKS:

SHRI RATANSINH RAJDA (Bombay South): Sir, under rule 377, I raise the following matter of urgent public importance:

India is a country where people enjoy freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion. Article 15 of our Constitution prohibits discrimination *inter alia* on grounds only of religion, race, caste, sex place of birth or any of them. Again, Article 26 of the Constitution grants to every religious denomination or any section thereof the right to manage their own religious affairs.

This House is perhaps aware that two sects of the Jain community, namely, Swetamber Jains and Digambar Jains are at loggerheads over the ownership of the religious temple, especially the Deity of Antarikshji at Shirpur, near Akola in Maharashtra.

There are frequent reports in the press that persons belonging to Swe-